not to eat *gutka,* that will be really very useful for the whole country ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज : * ...(**व्यवधान**)... सारा सदन यह प्रस्ताव पारित करे*

प्रो. राम देव भंडारी : *

श्री सभापति : ठीक है , ठीक है । नेक्स्ट क्वैश्चन । प्यारे लाल खंडेलवाल जी । ...(**व्यवधान**)...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सर, मुझे एक बात कहनी है *

श्री सभापति : आप अपना क्वैश्चन करिए, आप गुटखें के चक्कर में मत आइए ...(**व्यवधान**)...

दूध की कीमत

*244. **श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हमारे देश में पानी दूध से अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वार उक्त संबंध मे किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार पशुपालन के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने की संभावना पर विचार कर रही है;

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो पशुपालन के लिए बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी, नहीं । देश के दुग्ध उत्पादकों को उनके दुग्ध उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिल रहा है।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

(ख) और (ग) जी, नहीं। देश में प्रमुख ब्रांडों का बोतल बंद पानी 10 से 12 रूपए प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है जबकि देश में दूध की बिक्री मूल्य 15 से 21 रूपए प्रति लीटर है जो कि बोतल बंद पानी के मूल्य से अधिक है। राज्य सरकारों/राज्य दुग्ध संघो का दूध को मूल्य निर्धारित करने की स्वायत्तता है।

(घ) और (ड़) जी, नहीं। सरकार पशुपालन के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने की संभावना पर विचार नहीं कर रही हैं। तथापि, भारत सरकार एक राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार कर रही है जिसमें पशुपालन के कई पहलुओं को समाहित किया गया है।

(च) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग पशुपालन के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा हैः-

1. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना;

2. कुक्कुट विकास के लिए राज्यों की सहायता;

3. आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता;

4. सघन डेयरी विकास कार्यक्रम;

5. स्वच्छ तथा गुणवत्ता दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और

6. डेयरी/कुक्कुट उद्यम पूंजीगत कोष।

Price of milk

†*244 SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state

(a) whether it is a fact that the producers of milk are not getting the proper price of milk;

(b) whether it is also a fact that water is being sold at a price higher than milk in our country;

(c) if not, the details of efforts being made by Government in this regard;.

(d) whether Government are contemplating on the possibility of formulating a national policy on animal husbandry;

(e) if so, the details thereof: and

†Original notice of the question was received in Hindi.

(f) if not, the details of efforts being made for the development of the basic infrastructure for animal husbandry?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House

Statement

(a) No, Sir. The milk producers in the country are getting remunerative prices for the milk produced by them.

(b) and (c) No, Sir. The major brands of bottled water are being sold in the country at a rate ranging from Rs. 10 to Rs. 12 per litre, whereas sale price of milk in the country varies from Rs. 15 to Rs. 21 per litre which is higher than the price of bottled water State Governments/State Dairy Federations have autonomy to fix the prices of milk.

(d) and (e) No, Sir. Government is not contemplating the possibility of formulating National Policy on animal husbandry. However, Government of India is formulating a National Livestock Policy which covers several aspects of animal husbandry also.

(f) Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries is implementing the following schemes for the development of the basic infrastructure for animal husbandry:

1. National Project on Cattle and Buffalo Breeding.
2. Assistance to States for Poultry Development.
3. Assistance to States for Feed and Fodder Development.
4. Intensive Dairy Development programme.
5. Strengthening Infrastructure for Quality and Clean Milk Production.
6. Dairy/Poultry Venture Capital Fund.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : माननीय सभापति जी, सरकार ने मेरे प्रश्न के "क" भाग के उत्तर में कहा है कि दूध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल रहा है। मेरा कहना है कि सरकार का उत्तर ठीक नहीं है। आज की बढ़ी हुई मंहगाई में, दूध उत्पादक जो कि साधारणतः गरीब आदमी होता है, जब वह बाजार में पशु-आहार खरीदने जाता है, अपने लिए अनाज खरीदने जाता है, कपड़ा खरीदने जाता है, दवा खरीदने जाता है या बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसे बड़ी कठिनाई

होती है । महोदय, आज की मंहगाई के समय में दूध का भाव, जोकि उसके जीवन-यापन का एकमात्र साधन होता है, जब वह अपना दूध बेचने बाजार में जाता है तो उस को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता । महोदय, लाभकारी मूल्य का मतलब होता है कि सारा खर्च निकालने के बाद उसे कुछ बचत हो जाए, लेकिन वह बचा नहीं पाता । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दूध उत्पादक के लिए कम बैंक ब्याज रेट पर दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋण देने की योजना पर विचार करती हैं? दूसरे जो पशु-आहार बाजार में मिलता है, उस को सस्ते दाम पर चारा मिल जाए, खली मिल जाए और पशुओं को रखने के लिए सस्ती कीमत पर cloth मिल जाए, क्या इस के ऊपर सरकार विचार कर रही हैं?

श्री शरद पवार : महोदय, इस में दो बातें हैं, दूध की जो Selling price हैं । I have got the figures for all the months. But if you see the figures of November, the latest figures, the selling price of the milk per litre in Shimla is about sixteen rupees per litre; in Lucknow, it is twenty rupees; in Delhi, it is seventeen rupees; and in Ahmedabad, it is twenty rupees. So, the average price is about seventeen rupees and fifty seven *paise.* That is the average price of milk in most of the cities in the country. That is the reason why the reply has been given like this.

Now, the reply to the second question which has been asked is this. There are certain schemes which the Government of India has introduced through the State Government. For instance, suppose somebody wants to buy cows or buffaloes and wants to set up a small dairy, there is a scheme. As per that scheme, the Government of India, through NABARD, provides certain money to the farmers. But this scheme was started only last year. We would like to see the overall impact of the scheme for one or two years, and then we would like to expand the scheme.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अच्छी नस्ल के पुश देश में तैयार हों । मगर देखने में आया है कि अच्छी नस्ल के पशुओं की कमी है और साथ ही अच्छे वैटरनरी डाक्टर्स भी गांवों में उपलब्ध नहीं हैं । तीसरी बात यह कि जो पशु कसाई खाने में काटे जाते हैं, सरकार ने उस संबंध में कुछ कानून बनाए हैं कि कौनसे पशु कसाईखाने में भेजे जा सकते हैं और कौन से नहीं भेजे जा सकते हैं । सभापति महोदय, देखा यह गया है कि अच्छी नस्ल के दुधारू पशु कसाईखाने मे भेजे जाते हैं, जिस का परिणाम यह होता है कि दूध का उत्पादन कम होता है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे पशुओं को कसाईखाने में जाने से रोकने के लिए जो कानून हैं, क्या सरकार उनको और कठोर बनाने का विचार कर रही हैं, जिससे दूधारू पशु कसाईखाने में काटे जाने से रोके जा सकें?

श्री शरद पवार : इसमें पहला सवाल जो इस देश में दूध के उत्पादन के सम्बन्ध मे पूछा गया था, तो दूध का उत्पादन और बढाने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है । मगर हम यह भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि 1950-51 मेंtotal production was 90 million tonnes. Now, in the year 2006-07, the total production is 100 million tonnes. So, there is an improvement.

SHRI SHARAD PAWAR: But, the per-head use of milk has also definitely improved in the country. अब जहां तक दूसरा सवाल जो नस्ल इम्प्रूवमेंट करने के बारे में पूछा गया है, तो भारत सरकार ने National Project for the Cattle and Buffalo Breeding नाम की एक स्कीम तैयार की है, जिसके फर्स्ट फेज में हर राज्य को इसमें 402 करोड रूपए की राशि दी है और इसमें hundred per cent grant है। इस ग्रांट के माध्यम से जो प्रोग्राम लिया है, arrange delivery of vastly improved artificial insemination service at the farmers' doorstep, bring all breedable females among the cattle and buffaloes under organized breeding through artificial insemination or natural service by high quality bulls within a period of ten years, and undertake programme for indigenous, cattle and buffaloes so as to improve their genetic make-up as well as their availability, तो यह प्रोग्राम इसमें लिया गया है । यह प्रोग्राम 27 राज्यों में लिया गया है, उनको 402 करोड़ रूपए की राशि दी गई है और यह 100 परसेंट अनुदान हैं । इसके माध्यम से पशु सुधार करने के कार्यक्रम राज्य सरकारें जगह-जगह पर ले रही हैं । परन्तु इसमें सुधार करने की आवश्यकता है । जहां तक ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए । आपने जो दूध के सारे आंकडे दिए, उसमें मिलावटी दूध कितना है ।

श्री शरद पवार : सर, मिलावटी दूध या उसमें पानी कितना डालते हैं, इसकी information मेरे पास नहीं है । ...(**व्यवधान**)...

श्री रामदास अग्रवाल : मिलावटी तो सारा ही है, उसमें शुद्ध कितना है? ...(**व्यवधान**)...

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सभापति जी, ये जो उत्तर दे रहे हैं, वह अधूरा है।

SHRI SHARAD PAWAR: The last question raised was whether valuable cattle were being taken to *kasaikhana* or other places. The law that is prevailing in the country today is that valuable and useful cattle, especially cows, are not allowed to be taken; there is restriction. Various State Governments are taking effective steps. But, if there is a specific complaint

about any State, I am definitely willing to take it up with the concerned Government to take corrective action.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैं खुद एक किसान हूं, इसलिए मुझे दूध उत्पादन की व्यवहारिक कठिनाइयां मालूम है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : तब तो आपको यह भी मालूम होगा कि दूध निकलता कैसे हैं?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : जी हां, वह भी मालूम है। ...(**व्यवधान**)...

माननीय सभापति महोदय, इस देश के अदंर दूध के उत्पादन में एक बड़ी व्यावहारिक कठिनाई जो आ रही हैं, उसका कारण यह है कि हमारे यहां जो प्रजनन होता है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। होता यह है कि नर पशु ज्यादा पैदा हो जाते हैं और जो मादा पशु हैं, जो दूध का उत्पादन करते हैं, वे कम पैदा होते हैं। पिछले दिनों मैं एन.डी.आर.आई. National Dairy Research Institute. करनाल गया था, तब मैंने वहां के वैज्ञानिको से इस मुद्दे पर बात की। मुझे उनसे यह जानकारी मिली कि उन्होंने इस बात का एक प्रस्ताव वहां से भेजा है। अन्य देशों, जैसे नार्वे, स्वीडन और जो डच कंट्रीज है, जहां दूध के उत्पादन का काम बडे वैज्ञानिक स्तर पर किया जाता है, उन्होंने एक ऐसा genetically रास्ता निकाला है, जिससे वे नर और मादा पशुओं के उत्पादन पर, उनके प्रजनन पर नियंत्रण करने लग गए हैं। ऐसी किस्म के रिसर्च का एक प्रस्ताव यहां पर केन्द्र सरकार को नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीटयूट से प्राप्त हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ऐसे प्रस्ताव की जानकारी है? यदि नहीं, तो क्या वे ऐसे प्रस्तावों के बारे में जानकारी लेंगे और ऐसे अनुसंधान के लिए सरकार की ओर से जो आवश्यक स्वीकृति देनी है, क्या वह नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीटयूट को शीघ्र प्रदान करेंगे?

SHRI SHARAD PAWAR: I have not got any information of this type of a proposal sent by this, particular organizaiton, but definitely, I shall gather the information, and if there is some good proposal, we will be happy to support it financially.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA: Sir, I would like to know from the hon. Minister what are the steps being taken to improve milk yield by improving the cattle breed, provision of better veterinary care and by improved infrastructure facilities. What are the various efforts being made to develop poultry and fisheries to supplement the income of people who are depending on that?

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, the solution is that we have to improve the breed. There are two alternatives before us. One. we have to select

the excellent quality of indigenous breed and try to protect that indigenous breed, for example, take the cows like *Tharparkar, Sahiwal.* These are indigenous breeds, which are quite useful. Day by day, we are not getting a big number of these types of breeds. It is our responsibility to protect them. Certain programmes have been taken to expand and protect these types of breeds. Second thing is cross-breeding. A massive programme has been taken for that also. We have brought up to 20 per cent of cows in this country under cross breeding. But cross breeding is not a soulution. We should not totally depend on cross breeding. We have to keep a balance between cross breeding and indigenous breed. That is the overall thinking of the Government. Now, so far as various schemes are concerned, there are certain schemes which have been introduced by the Government of India like National Project for Cattle and Buffalo breeding, Foder Development, National Scheme for the Dairy Poultry Venture Capital Fund, Intensive Dairy Development Programme and Strengthening Infrastructure for the Quality and Clean Milk Production. In fact, this scheme has been recently introduced in October 2004 with initial provision of 30 per cent outlay. The objective of the scheme is to improve the quality of the raw milk produced and procured at the village level. Substantial financial support has been provided by the Government of India to the scheme.

*245. [The question(s) (SHRI RAJ KUMAR DHOOT was absent. For answer *vide* page 31.]

Fresh approvals for field trials of GM crops

*246. SHRI RAJEEV SHUKLA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the Government's response following a Supreme Court directive barring it from issuing fresh approvals of field trials of Genetically- Modified (GM) crops;

(b) whether Government propose to direct independent enquiry into the long term economic viability of GM crops in the Indian environment;

(c) If so, the details thereof; and

(d) If not, the reasons therefor?

THE MINISTER FOR ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI A. RAJA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.